गोरखपुर से प्रकाशित

RNI Reg. NO. UPBIL/2023/87841

साप्ताहिक

स्वदेशी इनक्रेडिबल

Web:www.sinews.in/E-mail: info@sinews.in

सिर्फ सच के साथ...

वर्ष : 03 अंक: 32 | गोरखपुर रविवार 01 फरवरी 2026 | मूल्य- 02 रूपया | पृष्ठ - 8

न्यूज

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस, वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1.7 डिग्री कम है। आईएमडी ने यह जानकारी दी। विभिन्न मौसम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार पालम में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 7.1 डिग्री सेल्सियस, रिज केंद्र पर 7.7 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में रात का तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 278 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

देश का चीनी उत्पादन अक्टूबर-जनवरी के दौरान 18.35: बढ़कर 1.95 करोड़ टन रहा

नयी दिल्ली। देश में चीनी उत्पादन चालू सत्र 2025-26 में 31 जनवरी तक 18.35 प्रतिशत बढ़कर 1.95 करोड़ टन पर पहुंच गया है। उद्योग निकाय इस्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्य उत्पादक राज्यों में उत्पादन बढ़ने से यह वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले सत्र की समान अवधि में चीनी का उत्पादन 1.64 करोड़ टन रहा था। चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। भारतीय चीनी एवं जैव-ऊर्जा विनिमार्ता संघ (इस्मा) के अनुसार, वर्तमान में देशभर में 515 चीनी मिलें चालू हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 501 मिलें चल रही थीं। देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक चीनी का उत्पादन 42 प्रतिशत बढ़कर 78.7 लाख टन रहा। राज्य में अभी 206 मिलों का परिचालन हो रहा है, जबकि एक साल पहले इनकी संख्या 190 थी। दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन अब तक 55.1 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग पांच प्रतिशत अधिक है।

अफसरी छोड़कर अलंकार घर पहुंचे तो मां ने गले लगाया

कानपुर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री शनिवार को कानपुर में अपने घर पहुंचे। केशव नगर स्थित आवास पहुंचते ही घर की महिलाओं ने शंखनाद से उनका स्वागत किया। मां गीता अग्निहोत्री ने माला पहनाकर गले से लगाया। समर्थकों ने भी अलंकार अग्निहोत्री को फूल-माला से लाद दिया। लोगों ने नारेबाजी की, देखो-देखो शेर आया,,। जमकर डांस किया। अलंकार ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। अलंकार ने कहा वह दो से तीन दिन में प्लान बनाकर शंकराचार्य से मिलने जाएंगे। फिलहाल शंकराचार्य की तरफ से दिए जाने वाले किसी पद को लेने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा हमारा अगला कदम देश का एक और काला कानून एससी-एसटी एक्ट की वापसी है। 95: फर्जी शिकायतें दर्ज होती हैं। सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य, भूमिहार और व्ठब वर्ग के लोग प्रताड़ित होते हैं। पैसों की वसूली की जाती है। 7 दिन में स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती तो हम आंदोलन के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा सोची-समझी साजिश के तहत यूजीसी एक्ट लाया गया था। 2027 के चुनाव को देखते हुए यह एक्ट लाया गया था। क्योंकि केंद्र सरकार की लड़ाई राज्य सरकार से है।

टीएमसी की विदाई का समय आ गया

बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे शाह, कार्यकर्ताओं में भरा जोश

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि अब बंगाल से टीएमसी की विदाई का समय आ गया है।

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस कड़ी में अब शनिवार को उत्तर 24 परगना में दिग्गज नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि अब टीएमसी की विदाई का समय आ गया है। इसी के गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोग टीएमसी को उखाड़ फेकेंगे। इनकी विदाई का समय आ गया है। इसी के साथ गृहमंत्री ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर वंदे मातरम के अपमान का भी आरोप लगाया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 'इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। पीएम मोदी की सरकार ने पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है, लेकिन विडंबना देखिए। जब बंगाल में जन्मे और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम पर संसद में चर्चा हुई, तो ममता बनर्जी के सांसदों ने चर्चा का विरोध किया।

क्या बंगाल की धरती वंदे मातरम के इस विरोध को बर्दाश्त कर सकती है? हमें यह संदेश बंगाल के हर व्यक्ति, हर वोटर, हर नागरिक तक पहुंचाना है कि ममता बनर्जी और टीएमसी वोट बैंक की राजनीति और घुसपैठियों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, 'वंदे मातरम का विरोध करके ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि वह बंगाल की पहचान और भारत के गौरव का विरोध कर रही हैं। मैं बंगाल के लोगों से अपील करता हूं कि अगले चुनावों में बंगाल की पहचान का विरोध करने वाली टीएमसी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकें और यहां देशभक्तों की सरकार लाएं।' वहीं आनंदपुर अग्निकांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आनंदपुर में लगी आग कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान चली गई है, और 27 लोग लापता हैं। यह घटना क्यों हुई? इस मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा है? मोमो फैक्ट्री के मालिक कौन हैं? मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके साथ फ्लाइट से विदेश गए हैं? और मोमो फैक्ट्री के मालिक को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर ये घुसपैठिए (मृतक) होते तो क्या ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती? बंगाली नागरिकों की हत्या हुई है।

महाराष्ट्र राजनीति में अब सुनेत्रा पवार का उदय

एजेंसी

नई दिल्ली। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने आज महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इससे पहले उन्हें एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया था जिसके बाद आज ही उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद यह प्रक्रिया हुई है। सुनेत्रा अजित पवार की पत्नी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी बन गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे, ये दोनों ही सुनेत्रा पवार की राष्ट्रीय विधानसभा की सहयोगी पार्टियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों तक सुनेत्रा पवार ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी थी। उस वर्ष हुए चुनावों में उन्होंने अपने पति की पार्टी की उम्मीदवार के रूप में बारामती से चुनाव लड़ा, लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई में अपनी भाभी और मौजूदा राष्ट्रीय विधानसभा सांसद सुप्रिया सुले से हार गईं। इसके बाद सुनेत्रा राज्यसभा के लिए चुनी गईं। सुनेत्रा पवार सामाजिक कार्य और सहकारी क्षेत्र से जुड़ी हैं, जिस पर पवार परिवार का दबदबा है। उन्होंने जैव रसायन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। समारोह से ठीक पहले, एनसीपी ने मुख्यमंत्री फडणवीस को सुनेत्रा पवार के विधायक दल के नेता के रूप में चुनाव के संबंध में एक पत्र सौंपा। प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल समेत एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने दक्षिण मुंबई स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'वर्षा' में उनसे मुलाकात की और उन्हें पत्र सौंपा। इसके बाद फडणवीस ने पत्र राज्यपाल आचार्य देवव्रत को भेज दिया। वहीं, एनसीपी और एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिवंगत अजित पवार की माता आशा पवार से काटेवाड़ी गांव स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कल बजट सत्र है, इसलिए मैं दिल्ली जा रही हूं। अभी-अभी मेरी आशा काकी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे अनुमति ली और पूछा कि क्या मुझे बजट सत्र के लिए दिल्ली जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हां, यह देश का बजट है, और आपको वहां जाना चाहिए। मैं एनसीपी की फ्लोर लीडर हूं, इसलिए मेरी उपस्थिति आवश्यक है।

[लापता]

नाम : विनोद सिंह

उम्र : 35 साल

रंग : काला लंबाई : 5 फीट 8 इंच

लापता होने स्थान : पुणे जंक्शन से ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर आने के लिए ट्रेन चेंज करने के दौरान हुए लापता!!

बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा !!

[Address] गाँव : गंगराई , थाना : श्यमदेउरवां

जिला : महाराजगंज

मोबाइल नं : 75710063340, 9569439554, 8960104755, 8423858173

सम्पादकीय...

अति आशावाद से बचें

देश में आम बजट से पहले सामने आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला व गतिशील बनाने पर बल दिया गया है। यह सर्वेक्षण उन चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है, जिनके लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर यानी जीडीपी के 7.4 रहने का भरोसा जताया गया है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास वृद्धि दर के 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान में सीमापरक तनाव, व्यापार में व्यवधान और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया है। निश्चित रूप से यह सावधानीपूर्वक दर्शाया गया आशावादी दृष्टिकोण घरेलू मांग, उपभोग और निवेश की मजबूती को ही दर्शाता है। इसके बावजूद कि तमाम बाहरी जोखिम विद्यमान हैं, मसलन टैरिफ को लेकर आपूर्ति श्रृंखला में तनाव व देश की अपेक्षाओं का संतुलन बनाना शामिल है। यह सार्थक है कि सर्वेक्षण यथार्थवाद को नजरअंदाज नहीं करता है, जो यह भी दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पूंजी प्रवाह व मुद्रा की ताकत से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती। यह भी हकीकत है कि एआई जैसी नई तकनीकों से होने वाले लाभ असमानता को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके लिये भी सहायक मानव संसाधन और विनियामक ढांचे की जरूरत होती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां श्रम शक्ति का बाहुल्य है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश होने का लाभ उठाएं। इसके लिये कौशल विकास को प्राथमिकता देने की सख्त जरूरत है, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों के जरिये विश्व में आर्थिक स्पर्धा का मुकाबला कर सकें। ये कदम हमारे निर्यात बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं। कालांतर में ये हमारे व्यापार घाटे को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वदेशी अभियान को तरजीह देने से लेकर रणनीतिक लचीलेपन और रणनीतिक अनिवार्यता भारत की आर्थिक क्षमता की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं की साख को अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाए। निस्संदेह, विश्व में भारतीय उत्पाद खरीदने के बारे में सोचने से स्थिति को बिना सोचे भारतीय उत्पाद खरीदने वाली सोच विकसित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इस स्थिति के लिये हमें विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता की सख्त जरूरत होगी। निस्संदेह, हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ संपन्न हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर अर्थव्यवस्था में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसके अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लटके हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। सर्वेक्षण में इस बाबत कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में इस एफटीए के सिरे चढ़ने की उम्मीद है।

राशिफल

मेषः- पुराने गलतियो से सीख लेते हुए वर्तमान को सुधारें। अच्छे कायरे से परिजनो के दिल में जगह बनावें। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न करें।

बृषभः- भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ति में असमर्थता जैसी पूर्वाग्रह मन में निराशा पैदा करेगी। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी।

मिथुनः- मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरे में न गंवायें। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ संभव। संवेदनशील शरीर ग्रहो की प्रतिकूलता से बिमार पड़ सकता है।

कर्कः- सब कुछ सामान्यतः ठीक होते हुए भी मन में अरुचितकर लगेगा। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट होगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

सिंहः- किसी की अस्वस्थता से परिवार में कष्ट का वातावरण रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यवश घर से दूर जाना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कायरे के प्रति आलस्य न करें, नुकशान हो सकता है।

कन्याः- प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन भाव उन प्रतिभाओं के लाभ से वन्चित हो सकता है। कल्पनाओं में जीना छोड़ कर भौतिक जगत के अनुरूप चलने का प्रयास करें।

तुलाः- योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। मस्त-मौला मन मौज मस्ती समय ब्यर्थ कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह होगा। शिक्षा-प्रतियोगिता में परिश्रम तिव्र होगा।

वृश्चिकः- नये घरेलू जिम्मेदारियें के पैदा होने से व्यय संभव। प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन अत्यंत प्रसन्न होगा। नये कायरे के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न शील बनें।

धनुः- नए क्षेत्रों मे प्रयास से लाभ संभव है। समस्याओ के समाधान से उत्साह में बृद्धि होगी। नए सम्बन्धों के सहयोग से आर्थिक कठिनाईयां दूर होंगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव।

मकरः- सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ति में असमर्थता जैसी पूर्वाग्रह मन में निराशा पैदा करेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव पहुंच सकता है।

कुंभः- किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा।

आवेश में लिया गया निर्णय से पश्चाताप का कारण बन सकता है। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी।

मोदी- दोनों हाथों में लड्डू

जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए चाहे जितने कठोर नियम बना ले, उन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ भी। यूजीसी द्वारा जारी नए नियमों पर देश भर में सवाल और बवाल दोनों खड़े हुए और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसे रोकने के लिए याचिकाएं दायर हुईं, जिन पर गुरुवार 29 जनवरी को महत्वपूर्ण सुनवाई भी हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहले दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि इन नियमों की भाषा में स्पष्टता की कमी है, जिससे उनका गलत उपयोग हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि ऐसे नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं और परिसरों में अमेरिका की तरह नस्लीय विभाजन जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नियमों की जांच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दुरुपयोग न हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों की समीक्षा करने को कहा और तब तक उनके लागू होने पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करें। जिसमें कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने पर विचार किया जाए, ताकि समाज में बिना भेदभाव के समग्र विकास हो सके।गौरतलब है कि यूजीसी नियमावली, 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। ये नियम अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लाए गए हैं। यह 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए गए हैं। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता समितियां (इक्विटी कमेटी) गठित करना अनिवार्य किया गया है। इस कमेटी का काम जातिगत भेदभाव की शिकायतों की जांच करना है। लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के हक की बात उठते ही समाज में बवाल खड़ा हो गया।भारत में जाति व्यवस्था इतनी गहरी पैठी हुई है कि जाति के नाम पर उत्पीड़न सामान्य व्यवहार के तौर पर अपना लिया गया है। एक इंसान दूसरे इंसान को केवल जाति के आधार पर अपमानित, शोषित या प्रताड़ित करे, यह चलन सदियों से चला आ रहा है और इसे दूर करने की जितनी कोशिशें की गईं, उतने ज्यादा अड़ंगे सवर्ण समाज की तरफ से लगाए गए। चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशें हों या अभी यूजीसी के नए नियम, उन पर समाज का एक तबका ऐसे विरोध में उतरा मानो अपने से निचली जातियों का उत्पीड़न उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण वर्ग की ओर से दायर याचिकाओं में इन नियमों को असंवैधानिक बताया गया है। इसे जाति आधारित भेदभाव करार दिया। याचिकाकताओं में से एक वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है और इससे शिक्षा क्षेत्र में, समाज में और अधिक खाई पैदा हो सकती है। कितने कमाल की बात है कि शिक्षा क्षेत्र या समाज में जातिगत भेदभाव इन लोगों को तब दिखाई नहीं देता, जब किसी दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग पंक्ति में बिठाने की खबरें आती हैं, या किसी छात्र को उसकी निचली जाति के कारण शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसे लोगों को अगर आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, तो उसके पीछे यही सदियों से चला आ रहा जातिगत भेदभाव ही है।बहरहाल, अब शीर्ष अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी। तब तक मोदी सरकार जाति या किसी और कारण से समाज को बांटने के नए तरीके सोच ही लेगी। वैसे तो शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने बचाव में कहा कि नए नियम किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाते हैं और समितियां निष्पक्ष होंगी, जिसमें विविध प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन सरकार इस बात को अच्छे से जानती थी कि कमजोर तबके के लोगों को सुरक्षा देने या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो भी फैसले लिए जाएंगे, उस पर समाज के सवर्ण तबके से तीखी प्रतिक्रिया आएगी ही और इस मामले पर राजनीति भी खूब होगी। और ऐसा ही हुआ भी। यूजीसी के नियम केवल कानूनी मसला नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और राजनैतिक पहलू भी हैं। जिनमें चुनावी हित नाप-तौल के ही मोदी सरकार आगे बढ़ी है। पूरे देश में यूजीसी के नए नियमों पर केवल विरोध ही नहीं हुआ, बल्कि नरेन्द्र मोदी-अमित शाह के पोस्टरों पर प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उनके खिलाफ कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। मजे की बात ये है कि इन नारों को लगाने वाले सवर्ण छात्रों को किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। जबकि जेएनयू में ऐसे ही नारे लगे थे तो छात्रों को फौरन देशविरोधी करार दिया गया था। जाति पर किस तरह का भेदभाव समाज में किया जाता है, ये उसी का एक उदाहरण है। बहरहाल, यूजीसी के नए नियमों को अभी लाना और फिर लागू होने पर रोक लगाना, सब चुनावी राजनीति की तरफ इशारा करते हैं। बिहार चुनाव में तो एसआईआर के कारण भाजपा को काफी मदद मिल गई। लेकिन तमिलनाडु, प.बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में भाजपा को तरकश में कुछ और तीर बढ़ाने थे। कांग्रेस जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा से आगे निकली हुई थी, अगले साल उत्तरप्रदेश में चुनाव हैं और वहां समाजवादी पार्टी भी पीडीए को आगे बढ़ाए हुई है। ऐसे में भाजपा को इनकी काट निकालनी थी, सो यूजीसी के नए नियमों से उसमें मदद मिल गई।

कुछ खास...

यू.जी.सी. इक्विटी रैगुलेशन, उलटी दिशा में सफर

मिहिर भोले

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वीरवार यू.जी.सी. विनियम 2026 पर स्टे लगाने के बाद देश के हर सामान्य नागरिक विशेषकर छात्रों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। उसकी जगह कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फिलहाल पूर्ववर्ती 2012 के नियम को लागू कर दिया है। मार्च के महीने में 2026 के विनियम पर विस्तृत सुनवाई होगी। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने इसके बारे में जो टिप्पणियां की हैं, वे काफी गंभीर और विचारणीय हैं। उन्होंने जाति से जुड़े कुछ आधारभूत प्रश्न किए हैं। यू.जी.सी. के इस भेदभावपूर्ण विनियम के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करती है। खंडपीठ ने कहा कि हमें एक जातिविहीन समाज की ओर बढना चाहिए लेकिन हम आजादी के 75 साल बाद भी जाति की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्या पिछले 75 वर्षों में हमने जो कुछ हासिल किया, उसको गंवाना चाहते हैं? यह चिंताजनक है। भारत का संविधान एक समावेशी समाज बनाने पर बल देता है। जातिवाद के खिलाफ हमने बड़े कदम उठाए हैं। जिस किसी को भी सुरक्षा की जरूरत है वह उसको मिलनी चाहिए। जहां तक इस विनियम का प्रश्न है, तो प्रथम दृष्टया यह अस्पष्ट दिखाता है। कानून के विशेषज्ञों को इसकी भाषा को स्पष्ट करने की जरूरत है। अपने वर्तमान स्वरूप में इस विनियम के दुरुपयोग की संभावनाएं हैं और यह संविधान की धारा 31 सी को चुनौती देता है। ये वही प्रश्न थे जो हर किसी को खटक रहे थे। वास्तव में उच्च शिक्षा व्यवस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज को बांटने वाले पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर ज्ञान, विवेक और मुक्त चिंतन को बढ़ावा दे। विश्वविद्यालय और कॉलेज विचारों के ऐसे मंच होते हैं, जहां व्यक्ति अपनी पहचान से पहले छात्र और फिर शोधकत्रा बनता है। दुर्भाग्यवश, यू.जी.सी. द्वारा प्रस्तावित इक्विटी रैगुलेशन 2026 इसी मूल भावना के विपरीत खड़ा दिखाई देता है। यह विनियम समानता के नाम पर भेदभाव की एक ऐसी इकतरफा और संकीर्ण परिभाषा गढ़ता है, जो समस्या के समाधान से अधिक, नई समस्याओं को जन्म देने वाली है। स्वयं मेरे लिए एक शिक्षक के रूप में यह मानना कठिन है कि कक्षा में खड़ा होकर कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जाति के चश्मे से देखता या उनसे कोई भेदभाव करता है। वर्षों तक पढ़ाने, मार्गदर्शन देने और शोध कराने के दौरान एक शिक्षक के लिए छात्र की पहचान उसकी जिज्ञासा, अनुशासन और बौद्धिक क्षमता से बनती है, न कि किसी सामाजिक वर्ग से। यही कारण है कि अधिकांश शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धियों में ईर्ष्या नहीं, बल्कि गर्व महसूस करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति-वर्ग से हों। जिस रोहित वेमुला प्रकरण के आलोक में इस एकतरफा कानून को बनाने की बात कही जा रही थी, उसकी सच्चाई खुद तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट में खुल चुकी है। यू.जी.सी. रैगुलेशन 2026 की सबसे गंभीर समस्या उसकी जातिगत भेदभाव की परिभाषा है। यह परिभाषा पहले ही यह मानकर चलती है कि शैक्षणिक परिसरों में भेदभाव एकतरफा होता है, यानी एक वर्ग स्वभावतरू उत्पीड़क है और दूसरा पीड़ित। यह दृष्टिकोण न केवल बौद्धिक रूप से आलसी है, बल्कि सामाजिक रूप से खतरनाक भी। क्या भेदभाव केवल एक ही दिशा में होता है? क्या अपमान, बहिष्कार, वैचारिक डूबहसा और सामाजिक तिरस्कार किसी एक ही वर्ग तक ही सीमित है? आज का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग है। जिन्हें हम पिछड़ा या दलित कह कर संबोधित करते हैं, वे अब देश और समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उच्चतम पदों पर आसीन हैं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं।

वो धुरंधर देखकर रो रहे थे..सारा ने बताया मूवी देखने के बाद क्या था पेरेंट्स का रिएक्शन, बोलीं- शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अर्जुन फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके यालिना जमाली के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इस फिल्म के बाद अब वह अपनी अगली तेलुगू फिल्म यूफोरिया की तैयारी में बिजी हैं। इसी बीच हाल ही में सारा ने बताया कि जब उनके पेरेंट्स ने धुरंधर देखी तो उनका क्या रिएक्शन था। हाल ही में सुमा कनकाला के साथ बातचीत में सारा अर्जुन ने कहा कि ये वो पल था जब उनके माता-पिता धुरंधर देखकर खुशी के आंसू रो रहे थे। एक्ट्रेस ने कहा, मेरे लिए ये सबसे खास दिन था। अपने माता-पिता की खुशी देखकर जो महसूस हुआ वो शब्दों में बताना मुश्किल है। जब पूछा गया कि क्या ये उनके पढ़ाई से जुड़ा था तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बिलकुल नहीं। ये सिर्फ धुरंधर से जुड़ा था। आगे सारा अर्जुन ने अपनी फिल्म जर्नी को लेकर बातचीत की और कहा, पॉन्नियिन सेल्वन के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल गई थी और प्लान था कि विदेश जाकर फिल्म और एक्टिंग की पढ़ाई करूं, लेकिन उसी बीच मैजिक साइन कर लिया। फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई जारी रखूंगी लेकिन जब यूफोरिया ऑफर आया तो कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मैं इसमें हिस्सा लेने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके बाद पीएस2, फिर मैजिक, फिर यूफोरिया और उसके बाद धुरंधर। सच कहूं तो मैंने धुरंधर साइन किया था जबकि मैं यूफोरिया की शूटिंग कर रही थी। बता दें, अब सारा अर्जुन जल्द ही तेलुगू फिल्म यूफोरिया में नजर आएंगी। ये फिल्म 6 फरवरी 2026 को कई भाषाओं में रिलीज होगी। इसके अलावा सारा धुरंधर पार्ट 2 में भी नजर आएंगी, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी।

एकता कपूर ने भूत बंगला के निर्देशक को उनके जन्मदिन पर मजेदार अंदाज में दी शुभकामनाएं

निर्देशक प्रियदर्शन के जन्मदिन के मौके पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें एक प्यारा और चुटीला संदेश देकर बधाई दी। उनका यह मजेदार विश एकदम भूत बंगला की ुनपताल`चपतपज को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर एकता ने फिल्ममेकर के लिए दिल से लिखा संदेश शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनने की खुशी जाहिर की और उस क्रिएटिव साझेदारी को फिर से याद किया, जिसे दर्शकों ने सालों से बेहद पसंद किया है। भूत बंगला के साथ, एकता कपूर एक ऐसी क्रिएटिव जुगलबंदी को फिर से साथ ला रही हैं, जिसे दर्शक लंबे समय से पसंद करते आए हैं। यह फिल्म उनकी एंटरटेनमेंट और नॉस्टैल्जिया से भरी कहानियों की यात्रा में एक और रोमांचक अध्याय जोड़ती है। प्रियदर्शन के लिए उनकी यह जन्मदिन की शुभकामना सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि उस रचनात्मक रिश्ते को दोबारा जीने की खुशी भी दिखाती है, जिसने भारतीय सिनेमा को कई यादगार पल दिए हैं। बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक डिवीजन) और केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं भूत बंगला। फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और प्रोड्यूसर्स हैं अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर। फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

विद्या बालन ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर प्रियदर्शन सर के जन्मदिन पर बनाई मजेदार वीडियो

भूल भुलैया की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं, जब ओरिजिनल मंजुलिका विद्या

बालन और अक्षय कुमार ने निर्देशक प्रियदर्शन को उनके जन्मदिन पर एक खास और मजेदार वीडियो के जरिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। यह वीडियो न सिर्फ हंसी से भरपूर था, बल्कि उस दौर की सिनेमाई जादू को भी फिर से जिंदा कर गया, जिसने दर्शकों के दिलों में एक दशक पहले ही खास जगह बना ली थी। इस छोटे से वीडियो में विद्या और अक्षय की सहज केमिस्ट्री और हल्का-फुल्का अंदाज साफ झलकता है। दोनों की बॉन्डिंग यह साबित करती है कि कुछ ऑन-स्क्रीन जोड़ियाँ वक्त के साथ फीकी नहीं पड़तीं, बल्कि समय के साथ और भी यादगार बन जाती हैं। फैंस के लिए यह वीडियो एक खूबसूरत थ्रोबैक है, जिसने "भूल भुलैया" की विरासत को एक बार फिर ताजा कर दिया।

भाई संग धन धन बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे में नतमस्तक हुईं शहनाज गिल, दोनों हाथ जोड़ मांगा आशीर्वाद

टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 से मशहूर होने के बाद बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल ने 27 जनवरी को अपना 32वां जन्मदिन मनाया। शहनाज ने अपना यह खास दिन अपने बेहद करीबी लोगों के साथ सादगी और खुशी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसकी एक झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। शहनाज गिल ने अपने जन्मदिन की शुरूआत आध्यात्मिक अंदाज में की। वह अपने भाई शहबाज बादेशा के साथ धन धन बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे पहुंचीं, जहां उन्होंने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस मौके की एक तस्वीर शहनाज ने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वह और उनके भाई गुरुद्वारे के बाहर हाथ जोड़कर खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों के सिर पर स्कार्फ बंधा हुआ है। तस्वीर के साथ शहनाज ने कैप्शन में लिखा, धन धन बाबा दीप सिंह जी। वाहेगुरु सब ते मेहर करेयो। इसके बाद शहनाज ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की झलकियां भी सोशल मीडिया पर साझा कीं। वीडियो में वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ केक काटती, डांस करती और खुलकर एंजॉय करती नजर आईं। उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि यह जन्मदिन उनके लिए बेहद यादगार रहा। काम की बात करें शहनाज गिल को आखिरी बार पंजाबी फिल्म इक्क कुड़ी में देखा गया था, जो अक्टूबर, 2025 को रिलीज हुई थी।

एक और सेलिब्रिटी हुई ब्रेस्ट कैंसर का शिकार, 30 की उम्र वालों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी?

ब्रेस्ट कैंसर दुनियाभर में तेजी से बढ़ते गंभीर और जानलेवा कैंसर में से एक है, कम उम्र की महिलाएं भी अब इसकी चपेट

में आरही हैं। साल 2022 में अकेले ब्रेस्ट कैंसर के कारण 6.70 लाख से अधिक महिलाओं की मौत हो गई। भारतीय आबादी में भी ये समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी महिलाओं को अलर्ट करते हैं।

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको की पूर्व कंटेस्टेंट जेलेन अल्वारेज भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई हैं। 33 साल की जेलेन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दी है। उनकी उम्र अभी 33 वर्ष है। सोशल मीडिया पर स्पेनिश में किए गए पोस्ट में उन्होंने आगे कहा, यह मौत का सामना करने जैसा है। ये आपकी मनोदशा का परीक्षा लेने वाला समय भी होता है।

33 साल की उम्र में कैंसर के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कम उम्र में ये जानलेवा बीमारी कैसे बढ़ती जा रही है और इसके समय रहते पहचान के लिए क्या किया जाना चाहिए?

स्तनों में गांठ होना, पहला संकेत

जेलेन कहती हैं, शुरू में मैंने इसके लक्षणों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद जब लगा कि स्तनों में गांठ है और इसका आकार बढ़ रहा है, तो चेक-अप के लिए गई। परिवार में पहले भी ऐसी बीमारी होने के बावजूद, जेलीन ने माना कि जब डॉक्टरों ने बीमारी की पुष्टि की तो वह पूरी तरह हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, मैं अभी ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हूं, जो महिलाओं में आम है। लेकिन, कम उम्र में इस बीमारी का शिकार होना मुझे हैरान करने वाला था।

जांच के दौरान पाया गया है कि उनका कैंसर शरीर में कहीं और नहीं फैला है। वह अब कीमोथेरेपी करवा रही हैं जिससे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके और इसे फैलने से रोका जा सके।

भारतीय सेलिब्रिटीज में ब्रेस्ट कैंसर के मामले

कई भारतीय सेलिब्रिटीज भी हाल के वर्षों में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो चुकी हैं।

आयुष्मान खुराना की पत्नी और फिल्म निमार्ता ताहिरा कश्यप दो बार ब्रेस्ट कैंसर से जूझ चुकी हैं। ताहिरा को पहली बार साल 2018 में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, जिसके बाद उन्हें मास्टेक्टॉमी करानी पड़ी थी। अप्रैल 2025 में उन्हें दोबारा ये बीमारी हो गई थी।

इसी तरह मशहूर अभिनेत्री अरुणा ईरानी भी दो बार स्तन कैंसर के चपेट में आ चुकी हैं। कोविड के दौरान उन्हें दूसरे बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया था।

कम उम्र वालों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी?

कुछ दशकों पहले तक ये बीमारी उम्र बढ़ने के साथ होने वाली मानी जाती थी। हालांकि अब 20-40 की उम्र वाली महिलाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं।

जिन महिलाओं के परिवार में पहले से किसी को स्तन कैंसर रहा हो उनमें BRCA1 और BRCA2 जैसे जीन म्यूटेशन के कारण कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने खतरा ज्यादा होता है

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बदलती जीवनशैली को भी इस बीमारी का प्रमुख कारण मानते हैं।

कम उम्र में मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और जंक फूड का ज्यादा सेवन हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है, जो स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, देर रात तक जागना, नींद की कमी और लगातार तनाव से शरीर में कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन प्रभावित होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास में भूमिका निभा सकते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, स्तन कैंसर से बचाव के लिए लाइफस्टाइल को ठीक रखना सबसे जरूरी है। नियमित व्यायाम करना, खानपान में सुधार और तनाव कम लेने से शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर संतुलित नियंत्रित रहता है और इम्युनिटी मजबूत होती है। संतुलित आहार जैसेहरी सब्जियां, फल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर चीजें कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करती हैं। जंक फूड, हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बनाना कैंसर से बचाव के लिए जरूरी है। शराब और धूम्रपान से भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इनसे भी पूरी तरह बचाव करना चाहिए।

क्या होता है 'ब्रेन रॉट'? आपके ब्रेन के लिए रील स्क्रॉल करना कितना खतरनाक?

'ब्रेन रॉट' एक ऐसा शब्द है जो आज की डिजिटल पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य की कड़वी हकीकत बयां करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'दिमाग का सुस्त होना', जो लंबे समय तक सोशल मीडिया पर कम गुणवत्ता वाले, बिना किसी अर्थ के और अत्यधिक उत्तेजक कंटेंट (जैसे रील्स और शॉर्ट्स) देखने के

कारण होने वाली मानसिक गिरावट को दशार्ता है।

इस शब्द की बढ़ती लोकप्रियता और प्रासंगिकता को देखते हुए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे वर्ष 2024 में 'वर्ड ऑफ द ईयर' घोषित किया। यह शब्द पहली बार इंटरनेट पर उभरा, लेकिन अब यह डिक्शनरी का हिस्सा बनकर उस स्थिति को परिभाषित करता है जहां व्यक्ति की सोचने, समझने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता क्षीण होने लगती है। जब हम घंटों रील स्क्रॉल करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सूचनाओं के अंतहीन प्रवाह में फंस जाता है, जिससे संज्ञानात्मक थकान और याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। आइए इस लेख में रील स्क्रॉल करने के कुछ साइड इफेक्ट जानते हैं।

रील स्क्रॉल करने की आदत और डोपामाइन लूप का साइंस

न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि रील्स का 'शॉर्ट-फॉर्म' फॉर्मेट मस्तिष्क में डोपामाइन का तेज प्रवाह पैदा करता है। इसे 'वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल' कहा जाता है, जो जुए की लत जैसा ही खतरनाक है। शोधकताओं के अनुसार, जब हम हर 15 सेकंड में नया कंटेंट देखते हैं, तो मस्तिष्क का 'प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स', जो निर्णय लेने और फोकस करने के लिए जिम्मेदार है, कमजोर होने लगता है, जिससे 'शॉर्ट अटेंशन स्पैन' की समस्या उत्पन्न होती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है गहरा असर

हालिया शोधों से पता चला है कि अत्यधिक रील स्क्रॉलिंग से 'डिजिटल डिमेंशिया' का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग दिन में 3 घंटे से अधिक रील देखते हैं, उनमें चिंता, अवसाद और अकेलेपन के लक्षण उन लोगों की तुलना में अधिक पाए गए हैं जो रचनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं। यह आदत मस्तिष्क के ग्रे मैटर के डेंसिटी को प्रभावित कर सकती है, जिससे सूचनाओं को प्रोसेस करने की गति धीमी हो जाती है।

ब्रेन रॉट के लक्षण और पहचान के तरीके

ब्रेन रॉट के प्रमुख लक्षणों में शामिल है, चीजों को जल्दी भूल जाना, पढ़ते समय ध्यान न भटकना, और बिना फोन के खाली बैठने पर बेचैनी महसूस होना। शोध बताते हैं कि रील स्क्रॉलिंग के दौरान मस्तिष्क सक्रिय होने के बजाय केवल 'पैसिव ऑब्जर्वेशन' मोड में चला जाता है। इससे रचनात्मक सोच खत्म हो जाती है और व्यक्ति हर समय मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता है, भले ही उसने कोई शारीरिक मेहनत न किया हो।

डिजिटल डिटॉक्स और सावधानी ही है एकमात्र उपाय

ब्रेन रॉट कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मगर इसे समय रहते रोकना जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों इससे समस्या से बचने के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' करने का सुझाव देते हैं और रील देखने के लिए दिन में केवल 20-30 मिनट का समय निर्धारित करें। सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बनाना और गहरी सोच वाले कार्यों (जैसे किताब पढ़ना) में समय बिताना आपके मस्तिष्क को फिर से स्वस्थ बना सकता है। ध्यान रखें कि तकनीक का उपयोग करें, उसे खुद पर हावी न होने दें।

फिर आने वाला है कोरोना जैसी महामारी का दौर! दो नए वायरस बढ़ा रहे हैं वैज्ञानिकों की चिंता

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और इंसानों-जानवरों के बीच बढ़ता संपर्क नई संक्रामक बीमारियों के जोखिम को बढ़ा रहा है। इन्फ्लूएंजा डी वायरस और कैनिन कोरोनावायरस दो नए वायरस बड़ी चिंता बनकर उभर रहे हैं।

साल 2019 के आखिरी के महीनों में दुनियाभर में फैले कोरोनावायरस संक्रमण ने कई साल तक अपना प्रकोप दिखाया। कोरोनावायरस महामारी ने दुनिया को यह साफ तौर पर दिखा दिया कि कोई भी संक्रामक बीमारी कितनी तेजी से वैश्विक संकट का रूप ले सकती है। इस आपात स्थिति के चलते स्वास्थ्य प्रणालियां चरमरा गईं, अर्थव्यवस्थाएं ठप हो गईं और आम जनजीवन पूरी तरह बदल गया।

लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे शब्द हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। इस महामारी ने न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर भी गहरा असर डाला। क्या ऐसी ही परिस्थितियां दोबारा से बनने वाली हैं? वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां भविष्य की संभावित महामारियों को लेकर लगातार चेतावनी दे रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और इंसानों-जानवरों के बीच बढ़ता संपर्क नई संक्रामक बीमारियों के जोखिमों को बढ़ा रहा है। एक हालिया रिपोर्ट में वैज्ञानिकों की टीम ने अलर्ट किया है कि इंसानों की सेहत के लिए दो नए वायरस बड़ा खतरा बनकर उभर सकते हैं। शोधकताओं ने अलर्ट किया है कि ये दोनों वायरस सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं और इनके कारण एक और महामारी आने की भी आशंका है।

दो नए वायरस को लेकर अलर्ट

यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को एक नई महामारी के खतरे को लेकर सावधान किया है। विशेषज्ञों ने कहा, जानवरों से आए दो नए वायरस अभी तक लोगों की नजर में ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन अध्ययनों में इनकी प्रकृति को देखकर लगता है कि ये भविष्य में महामारी और पैनडेमिक का खतरा पैदा कर सकते हैं।

टीम ने कहा, इन्फ्लूएंजा डी वायरस और कैनिन कोरोनावायरस दोनों बड़ी चिंता के रूप में देखे जा रहे हैं। इनको लेकर बेहतर निगरानी, डायग्नोस्टिक्स और इलाज की खोज तेज करने की जरूरत है। दोनों ही वायरस जानवरों के माध्यम से फैलने वाले माने जा रहे हैं। इंसानों में इसका प्रसार काफी तेजी से होने की आशंका है, जिसको लेकर पूरी दुनिया को पहले से ही सावधान हो जाने की जरूरत है ताकि कोरोनावायरस के संक्रमण जैसा दौर फिर से न आने पाए।

वैज्ञानिकों ने नई महामारी को लेकर किया सावधान

जर्नल इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित इस रिपोर्ट में शोधकताओं ने अलर्ट किया है कि कोरोनावायरस की ही तरह से ये दोनों वायरस भी इंसानों में श्वसन समस्याओं को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति के हो सकते हैं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ प्रोफेशन में एनवायरनमेंटल एंड ग्लोबल हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जॉन लेडनिकी कहते हैं, हमारी समीक्षा से पता चलता है कि ये दोनों वायरस इंसानों के लिए सांस की बीमारी का खतरा पैदा करते हैं। चूंकि इन वायरस के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इससे होने वाले संक्रमण की रोकथाम और इलाज के लिए अभी बहुत कम काम किया गया है। अगर ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो ये महामारी फैला सकते हैं। ज्यादातर लोगों में इनके प्रति इम्युनिटी नहीं होगी, ऐसे में ये वायरस न सिर्फ तेजी से बढ़ सकते हैं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य संकट भी पैदा करने वाले हो सकते हैं।

अब तो शर्म करो पाकिस्तान! आइसलैंड के बाद युगांडा ने भी उड़ाया मजाक, रिप्लेसमेंट बनने को तैयार

एजेंसी

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान के संभावित बहिष्कार की चर्चाओं पर अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में खुला मजाक बनने लगा है। पहले

आइसलैंड और अब युगांडा क्रिकेट ने पाकिस्तान की जगह टूर्नामेंट में खेलने की पेशकश कर दी है, वह भी व्यंग्य और तंज के अंदाज में। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की स्थिति और असहज होती जा रही है।

युगांडा ने सोशल मीडिया पर किया तंज

युगांडा क्रिकेट के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट ने 29 जनवरी को एक पोस्ट के जरिए पाकिस्तान पर सीधा तंज कसा। पोस्ट में लिखा गया, 'अगर टी20 वर्ल्ड कप में कोई सीट खाली होती है, तो युगांडा पूरी तरह तैयार है, पैक्ड और पैडेड। पासपोर्ट गर्म हैं (बर्फ जैसे ठंडे नहीं)। कोई बेकर ओवन छोड़कर नहीं जा रहा, न ही कोई जहाज यू-टर्न लेगा। गर्मी, शोर, दबाव? हम बोल्ड किट लेकर आएंगे।' यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और क्रिकेट फैंस ने इसे पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश माना। साथ ही यह आइसलैंड के ट्वीट का भी जवाब था। आइसलैंड ने युगांडा के मजे लिए थे।

पाकिस्तान के बहिष्कार की अटकलें क्यों?

दरअसल, पाकिस्तान द्वारा टी20 वर्ल्ड कप से हटने की अटकलें इसलिए तेज हुईं क्योंकि पीसीबी ने बांग्लादेश के समर्थन में एकजुटता दिखाने के संकेत दिए थे। बांग्लादेश ने भारत में खेले जाने वाले मैचों को लेकर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वेन्यू को श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी। आईसीसी द्वारा यह मांग ठुकराए जाने के बाद बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटाने का फैसला लिया। इसके बाद पाकिस्तान को लेकर भी कयास शुरू हो गए कि वह भारत के खिलाफ मैच या पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है।

पहले आइसलैंड, अब युगांडा... शर्म करो पाकिस्तान!

युगांडा से पहले आइसलैंड क्रिकेट ने भी पाकिस्तान को ट्रोल किया था। आइसलैंड क्रिकेट ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वे पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें पहले से सूचना मिल जाए।आइसलैंड की इस पोस्ट को पांच लाख से ज्यादा इम्प्रेशंस मिले, जिसके बाद उन्होंने कोलंबो के बढ़ते फ्लाइट किरायों पर भी चुटकी ली। बाद में आइसलैंड ने खुद ही टूर्नामेंट से नाम वापस लेते हुए एक और मजेदार बयान जारी किया था और युगांडा पर तंज कसा था। युगांडा के कुछ पॉइंट्स आइसलैंड की ट्वीट का जवाब भी थे।

आइसलैंड ने पहले क्या लिखा था?

आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर लिखा, 'हमें वाकई पाकिस्तान से टी20 विश्व कप में भाग लेने के बारे में जल्द फैसला लेने की जरूरत है। जैसे ही वे दो फरवरी को नाम वापस लेंगे हम तुरंत रवाना होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उड़ान का शेड्यूल इतना जटिल है कि सात फरवरी तक कोलंबो समय पर पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा।' इतना ही नहीं आइसलैंड क्रिकेट ने उनके ट्रेवल प्लान का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया।

आइसलैंड ने फिर नाम लिया वापस

आइसलैंड क्रिकेट ने कहा, 'हमारे खिलाड़ी अलग-अलग पेशों से आते हैं और अचानक दुनिया के दूसरे छोर पर नहीं जा सकते। हमारा कप्तान एक पेशेवर बेकर है, जिसे ओवन संभालना है। हमारा जहाज कप्तान समुद्र में है, और हमारे बैंकर... फिर से दिवालिया होने की तैयारी में हैं।

बांग्लादेश-पाकिस्तान के ड्रामे पर सुरेश रैना का करारा वार! नकवी की गीदड़भभकी पर बोले- ICC छोड़ेगा नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2026 को बहिष्कार करने की पाकिस्तान की गीदड़भभकियों पर भारत के पूर्व स्टार और विश्व कप विजेता क्रिकेटर सुरेश रैना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रैना ने इस पूरे संकट के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट से दूर रहने की सोच उन्हें काफी महंगी पड़ सकती है।

बांग्लादेश विवाद की जड़ और आईसीसी का फैसला

विवाद तब भड़का जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत आने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने उनकी मांग खारिज की और अंततः बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। रैना ने सुरक्षा दावों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भारत में सभी इंतजाम मौजूद थे। रैना ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'भारत में सुरक्षा पूरी थी, सब कुछ मौजूद था। जो बांग्लादेश के साथ हुआ, उसमें गलती उन्हीं की है।'

'भारत आते तो बहुत कुछ मिलता'

रैना का मानना है कि बांग्लादेश ने क्रिकेटिंग नजरिए से भी बड़ा नुकसान किया। उन्होंने कहा, 'अगर बांग्लादेश भारत आता तो तस्वीर अलग होती। उनकी टीम बहुत मजबूत है, खासकर स्पिनर्स यहां की परिस्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं। वे बहुत कुछ खो देंगे।' अपने अनुभव साझा करते हुए रैना ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2016 टी20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया और भारत के माहौल को त्योहार बताया। रैना ने कहा, 'भारत में वर्ल्ड कप खेलना किसी त्योहार से कम नहीं होता। हर टीम को इसका हिस्सा बनना चाहिए।'

मोहसिन नकवी को सीधी चेतावनी

पाकिस्तान द्वारा एकजुटता बहिष्कार या भारत के खिलाफ मैच न खेलने की अटकलों के बीच रैना ने पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी को साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा, 'आईसीसी चेयरमैन पहले ही साफ कह चुके हैं- जो टीमें भारत नहीं आएंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।' रैना ने यह भी जोड़ा कि भारत में नहीं खेलने का मतलब है व्यावसायिक और सांस्कृतिक तौर पर भारी नुकसान उठाना।

डिफेंडिंग चैंपियन भारत, फिर दूरी क्यों?

रैना ने कहा कि जब भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और दुनिया की टॉप टीम है, तो उससे बचना फैंस और क्रिकेट, दोनों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा, 'ऐसे टूर्नामेंट से दूर रहना, जहां सबसे बेहतरीन क्रिकेट होता है, किसी के हित में नहीं।'

ICC का सख्त रुख, बड़े प्रतिबंधों की आशंका

रैना की बातें आईसीसी के कड़े रुख से मेल खाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी बहिष्कार करने वाली टीमों पर अभूतपूर्व प्रतिबंध, यहां तक कि सदस्यता निलंबन जैसे कदम भी उठा सकता है। पीसीबी को या तो शुक्रवार या फिर दो फरवरी को अंतिम फैसला लेना है और रैना का संदेश स्पष्ट है: दूर रहने की कीमत बहुत भारी है।

ट्रंप ने केविन वॉर्श को सौंपी फेडरल रिजर्व की कमान, जेरोम पॉवेल की लेंगे जगह

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह फेडरल रिजर्व के अगले चेयर के रूप में पूर्व फेड अधिकारी केविन वॉर्श को नामित

करेंगे। अगर सीनेट से मंजूरी मिलती है, तो वॉर्श मई में मौजूदा चेयर जेरोम पॉवेल की जगह लेंगे। यह फैसला अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीति दिशा में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जिससे फेड को व्हाइट हाउस के करीब लाने और उसकी लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की आशंका जताई जा रही है।

ट्रंप ने 2017 में जेरोम पॉवेल को फेड चेयर नियुक्त किया था, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने ब्याज दरों में तेजी से कटौती न करने को लेकर पॉवेल की लगातार आलोचना की।

55 वर्षीय केविन वॉर्श पहले भी फेडरल रिजर्व बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 2006 से 2011 तक फेड में सेवा दी और 35 वर्ष की उम्र में नियुक्त होकर फेड के इतिहास के सबसे युवा गवर्नर बने। वर्तमान में वह रूढ़िवादी विचारधारा वाले हूवर इंस्टीट्यूशन में फेलो हैं और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं।

क्या घटने वाली है महंगाई दर? इस बड़े बदलाव से रोजमर्रा की चीजें हो सकती हैं सस्ती

एजेंसी

नई दिल्ली। आम लोगों की रोजमर्रा की महंगाई को मापने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के नियम बदलने जा रहे हैं। सरकार ने सीपीआई का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2023-24 कर दिया है, जिससे महंगाई के आंकड़ों में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नए वेटेज लागू होने पर कुल महंगाई दर में करीब 20-30 आधार अंकों की मामूली बढ़ोतरी हो

सकती है।

क्या है रिपोर्ट का दावा?

रिपोर्ट में कहा गया है कि पुराने इंडेक्स पर नए वेटेज लागू करने से कुल महंगाई में हल्की बढ़ोतरी दिखती है। हालांकि, जिन महीनों में खाद्य महंगाई ज्यादा होगी, उन महीनों में नया सीपीआई पुराने सीरीज की तुलना में 20-30 आधार अंक कम भी हो सकता है।

यह आकलन सीपीआई के बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2023-24 करने की प्रक्रिया के बीच सामने आया है। बदलते उपभोग पैटर्न और वैश्विक मानकों के अनुरूप महंगाई माप को अधिक सटीक बनाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था, जिसकी सिफारिशें हाल ही में जारी की गई हैं।

नई सीपीआई सीरीज में क्या किया गया बदलाव?

नई सीपीआई 2024 सीरीज में कुल 358 वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिन्हें 12 डिवीजन, 43 समूह, 62 वर्ग और 192 उप-वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

नई सीरीज के तहत पहला सीपीआई डेटा 12 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा, जिसमें जनवरी 2025 से इंडेक्स डेटा और जनवरी 2026 की महंगाई दर शामिल होगी।

इसके साथ ही ग्रामीण, शहरी और संयुक्त स्तर पर जनवरी 2013 से बैक सीरीज डेटा भी जारी किया जाएगा।

सीपीआई के वेटेज स्ट्रक्चर में क्या हुए बदलाव?

बेस ईयर संशोधन के साथ सीपीआई के वेटेज स्ट्रक्चर में भी अहम बदलाव हुए हैं। खाद्य व पेय पदार्थों का वजन पुराने 45.86 से घटकर 36.75 हो गया है, जबकि आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन का वजन 16.91 से बढ़कर 17.66 हो गया है। परिवहन, सूचना और संचार का वजन 8.59 से बढ़कर 12.41 हो गया है। वहीं स्वास्थ्य, घरेलू सामान और रखरखाव व व्यक्तिगत देखभाल व अन्य सेवाओं के वजन में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये बदलाव उपभोक्ताओं के बदलते खर्च पैटर्न को दर्शाते हैं और भविष्य में महंगाई के अधिक सटीक आकलन में मदद करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

गांधी जी ने संदेश दिया,बिना हिंसा भी परिवर्तन संभव:केशव

लखनऊ(संवाददाता)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा,राष्ट्रपिता महात्मा

गांधी केवल एक व्यक्ति नही बल्कि एक विचार, एक दर्शन और भारत की आत्मा थे। सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा के जिन मूल्यों पर उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया, वही मूल्य आज भी हमारे राष्ट्र के पथप्रदर्शक हैं।महात्मा गांधी ने अपने तप, संघर्ष और आत्मबल से न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्थायी शांति और न्याय की स्थापना की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश "स्वच्छ भारत", "आत्मनिर्भर भारत" और "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कहीं न कहीं गांधी जी के विचारों का ही आधुनिक स्वरूप है।प्रदेशवासियों से आान करता हूँ कि हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलकर एक सशक्त, समरस और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान दें।

खराब मौसम से लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द, दुबई और खजुराहो की फ्लाइट रद्द

लखनऊ(संवाददाता)।खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण लखनऊ एयरपोर्ट से संचालित होने वाली तीन उड़ानों को शुक्रवार को रद्द करना पड़ा। अचानक बदले मौसम के चलते एयरलाइंस को एहतियातन यह फैसला लेना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट सूत्रों की मानें तो सुबह से ही मौसम अनुकूल नहीं है। कोहरे और बादलों की घनी परत के कारण रनवे पर दृश्यता मानक स्तर से नीचे चली गई। इसी वजह से सुबह 10.10 बजे जार्जटाउन (जेआरजी) के लिए रवाना होने वाली एस 5 228 उड़ान को निर्धारित समय पर ही रद्द कर दिया गया। खराब मौसम का असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी देखने को मिला। 11.30 बजे दुबई (डीएक्सबी) के लिए प्रस्तावित आईएक्स194 उड़ान को भी सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मौसम में तत्काल सुधार की संभावना न होने के चलते एयरलाइंस ने उड़ान निरस्त करने का निर्णय लिया। दिनभर मौसम की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो सका। इसके चलते शाम 4.55 बजे खजुराहो (केएचक्यू) के लिए निर्धारित एस 5 222 उड़ान को भी रद्द करना पड़ा। लगातार उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई और लोग जानकारी के लिए एयरलाइंस काउंटरों के चक्कर लगाते रहे। उड़ानें रद्द होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल दिखा। कई यात्री जरूरी कामों से यात्रा कर रहे थे, जिन्हें अचानक योजना बदलनी पड़ी। एयरलाइंस काउंटरों पर री-शेड्यूलिंग और रिफंड को लेकर लंबी कतारें देखी गईं।

कैफे में ग्राहक को कलछुल-फ्राईदान से पीटा, पुलिस ने 10 को उठाया

लखनऊ(संवाददाता)।हजरतगंज के एक कैफे में ग्राहक को कैफे के कर्मियों ने जमकर पीटा। किसी बात पर बहस हो गई तो छन्नी-कलछुल-फ्राईदान-भगोने से जमकर पीटना शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। कैफे के अंदर एक युवक को कई लोग मिलकर हाथ-पैर और बर्तनों से मार रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 10 युवकों को हिरासत में ले लिया है। मामला ग्लोब कैफे का गुरुवार रात का है। वीडियो में दिख रहा है कि कैफे के अंदर अचानक हुई इस मारपीट से अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। यह पूरी घटना बाहर से किसी ने रिकॉर्ड कर ली। मामले को संज्ञान में लेते हुए हजरतगंज थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अब तक 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हजरतगंज जैसे वीवीआईपी और पॉश इलाके में देर रात तक कैफे खुले रहने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। ग्लोब कैफे में इससे पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस की चेतावनी और हिदायत के बावजूद कैफे संचालक नियमों को ताक पर रखकर दुकान खोलते हैं। इसके अलावा कैफे के बाहर सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे राहगीर परेशान होते हैं।

पुलिस बूथ के पास 5 कारों की बैटरियां चोरी

लखनऊ(संवाददाता)।पारा थाना क्षेत्र के भपटामऊ गांव में चोरों ने बीती रात पांच कारों की बैटरियां चोरी कर लीं। यह घटना घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से सुबह करीब 4 बजे हुई। चोरी की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पीड़ित तारिख खान ने पारा थाना में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उनके घर के पास खुले मैदान में रोजाना की तरह 6 से 7 गाड़ियां खड़ी थीं। चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक गाड़ियों से बैटरियां निकाल लीं। सीसीटीवी फुटेज में वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई एक सैंट्रो कार साफ दिखाई दे रही है। पीड़ितों के पास फुटेज और तस्वीरें मौजूद हैं। जिन गाड़ियों से बैटरियां चोरी हुई हैं, उनमें तारिख खान, मुनीर खान, मोहम्मद शारिक, करीम खान और नफीस शामिल हैं। चोरी की लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश है।

अब मंत्री देंगे 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को वित्तीय स्वीकृति

लागत में 15 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी पर पुनः अनुमोदन अनिवार्य:योगी

लखनऊ(संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल

और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली स्वीकृति की सीमा, जो अभी 10 करोड़ रुपये तक है, उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जाए। 50 से 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री स्तर से और 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर से दी जाए, जिससे परियोजनाओं को समय पर वित्तीय मंजूरी मिले और काम तेजी से आगे बढ़े।मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक हर हाल में स्वीकृत करा लें। समयसीमा का पालन न करने वाले विभागों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। किसी परियोजना की लागत में 15 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी होने पर विभाग कारण सहित पुनः अनुमोदन प्राप्त करें।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वित्त विभाग की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राज्य की राजकोषीय स्थिति, बजट प्रबंधन, पूंजीगत व्यय, निर्माण कार्यों की व्यवस्था, एकमुश्त प्रावधान, डिजिटल वित्तीय सुधार, कोषागार प्रक्रियाएँ, पेंशन व्यवस्था और विभागीय नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की उत्तर प्रदेश को सुदृढ़, पारदर्शी, रिजल्ट ओरिएंटेड वित्तीय प्रबंधन का आदर्श राज्य बनाना है। इसके लिए विभाग समयबद्धता, गुणवत्ता, पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य गारंटी पॉलिसी लागू की जाए। अल्प-वेतनभोगी कर्मियों, जैसे आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर माह तय तारीख को उनके बैंक खातों में पहुंच जाए। जिन योजनाओं में केंद्रांश मिलता है, वहां राज्य अपने मद से मानदेय समय पर जारी करे ताकि किसी कर्मी को देरी न हो। 2023-24 में यूपी का 1,10,555 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय देश में सबसे अधिक रहा। राज्य ने जितना शुद्ध लोक ऋण लिया, उससे भी ज्यादा राशि पूंजीगत कार्यों पर खर्च की, जो वित्तीय अनुशासन का मजबूत संकेत है। कुल व्यय का 9.39 फीसदी निवेश पर खर्च कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ऋण जीएसडीपी अनुपात जैसे सभी संकेतक एफआरबीएम मानकों के अनुरूप रहे। वर्ष 2024-25 में राज्य की कुल देयताएं घटकर जीएसडीपी के 27 फीसदीपर आ गईं। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश का कंपोजिट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2014 में 37 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया है और राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में पहले स्थान पर है। आरबीआई की रिपोर्ट में भी राज्य का अपना कर राजस्व राष्ट्रीय हिस्सेदारी में 11.6 फीसदी के साथ देश में दूसरे स्थान पर बताया गया है। विकास व्यय राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है और स्वास्थ्य व्यय में उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर है। वित्त विभाग ने पिछले तीन वर्षों में बजट, कोषागार और डिजिटल वित्तीय प्रशासन में ऑनलाइन बजट मॉड्यूल, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर ट्रेजरी, पूरी तरह ऑनलाइन बिल प्रेषण, जीपीएफ अनियमितताओं की रोकथाम, वेतन बिलों का एजी को ऑनलाइन भेजना, डिजिलॉकर पर जीपीएफ स्लिप उपलब्ध कराना जैसे कई सुधार किए है। कोषागार सुधारों के तहत साइबर ट्रेजरी के माध्यम से खातों का पूर्णतरू पेपरलेस प्रेषण अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स विभाग के नवाचारों के बारे में बताया गया कि विभाग ने प्रमुख सेवाओं को डिजिटल किया है। पुराने अभिलेख डिजिटल हो रहे हैं। रसादरश पोर्टल के माध्यम से जनता को अभिलेखों तक आसान पहुँच मिली है। वाद प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है और नीति आयोग के "दर्पण" पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंधों में एकरूपता का अभाव है। सड़क निर्माण की तर्ज पर नए भवनों में 5 वर्ष का भुगतान आधारित अनुरक्षण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। पुराने भवनों के अनुरक्षण के लिए कॉर्पस फंड बनाने की आवश्यकता बताई निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भवन, सड़क, सेतु, सीवर लाइन और जलापूर्ति पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं का थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट आईआईटी, एनआईटी और राज्य,सरकारी तकनीकी संस्थानों से कराया जाए। उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन, पूंजीगत व्यय और राजस्व संवर्धन में देश में नया मानक स्थापित किया है। अब लक्ष्य है कि खर्च की गुणवत्ता और डिजिटल पारदर्शिता को और मजबूत करते हुए प्रदेश को भारत का सबसे सक्षम और विश्वसनीय वित्तीय प्रशासन वाला राज्य बनाया जाए।

राजधानी में लौटी शीतलहर, बादल छाए,1 फरवरी से बारिश के आसार

लखनऊ(संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में हल्की बारिश के बाद फिर कोहरा और शीतलहर का दौर लौट आया है। शुक्रवार सुबह हल्की धुंध के साथ कोहरे का असर बना रहा। सुबह से ही बर्फीली हवा चल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। गुरुवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा। दिन भर ठंडी हवा चलती रही। अधिकतम आर्द्रता 95 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 66 फीसदी रही है।अब बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों से ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 31 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में और थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। वायुमंडल में स्थिरता बढ़ने से कोहरे की मात्रा और घनत्व में इजाफा होगा, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है। कई इलाकों में घना कोहरा छाने से लोगों को सावधानी बरतनी होगी, खासकर सड़क यात्रा के दौरान।

राष्ट्रपिता की पुण्य तिथि पर सीएम योगी ने बापू को किया नमन

लखनऊ(संवाददाता)।राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीपीओ पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर

पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धा व सम्मान के वातावरण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को नमन किया। इसके बाद कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने राष्ट्रपिता को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आमजन से उनके आदर्शों को अपनाने का आान किया।श्रद्धांजलि समारोह के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी गई। "रघुपति राघव राजाराम" सहित अन्य भजनों की मधुर धुनों से जीपीओ पार्क गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकाग्रता के साथ लगभग 15 मिनट तक बैठकर भजनों को सुना। इस दौरान उन्होंने न केवल बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की, बल्कि गांधी प्रतिमा के समक्ष सभी स्कूली बच्चों के साथ फोटो भी खिंचाई।

अखिल भारतीय विज्ञान मेला 2026 हेतु दो दिवसीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ

गोरखपुर। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में 'अखिल भारतीय विज्ञान मेला 2026' की पूर्व तैयारी हेतु दो दिवसीय 'पाठ्यक्रम निर्माण कार्यशाला' का भव्य शुभारंभ आज सरस्वती शिशु मंदिर,(10+2) पक्कीबाग के परिसर में हुआ। कार्यशाला के प्रथम दिन मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित विद्या भारती के अखिल भारतीय विज्ञान संयोजक श्री नगेंद्र पाण्डेय ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान मेला केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार (Innovation) विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2026 के विज्ञान मेले का पाठ्यक्रम वर्तमान वैश्विक तकनीकी परिवर्तनों और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के अनुरूप होना चाहिए। शिशु शिक्षा समिति, गोरक्ष प्रांत के प्रांतीय मंत्री डॉ. शैलेश सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल शिक्षकों की क्षमता का विकास होता है, बल्कि यह भविष्य के वैज्ञानिकों की तैयारी की आधारशिला भी रखता है। उन्होंने गोरक्ष प्रांत में विज्ञान शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु निरंतर प्रयास करने की बात दोहराई। आगामी अखिल भारतीय विज्ञान मेले के लिए मानक पाठ्यक्रम, नियमावली और नए प्रयोगों का चयन करने पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में पूरे देश के 11 क्षेत्र के विज्ञान संयोजक एवं सहसंयोजक एवं गोरक्ष प्रांत के विज्ञान विशेषज्ञ और अनुभवी आचार्य प्रतिभाग कर रहे हैं। कल, 30 जनवरी को कार्यशाला के समापन सत्र में आगामी कार्ययोजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय संयोजक बांके बिहारी जी, प्रदेश शिक्षक राम सिंह, जियालाल जी, संभाग निरीक्षक कन्हैया चौबे सहित देश के कोने-कोने से आए हुए विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चनसे हुआ ।अतिथि परिचय एवं सम्मान प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश सिंह जी द्वारा हुआ ।

कैंब्रिज हाई स्कूल एंड कॉलेज शंकरगढ़ में भव्य वार्षिकोत्सव का आयोजन

मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि नीरज त्रिपाठी ने दिए प्रमाण पत्र व गोल्ड मेडल

शंकरगढ़। नगर पंचायत स्थित कैंब्रिज हाई स्कूल एंड कॉलेज शंकरगढ़ में भव्य वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक संतोष त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व अपर महाधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय नीरज त्रिपाठी रहे। मुख्य अतिथि नीरज त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। विशेष रूप से वृद्धा आश्रम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाटकों को देखकर कई अतिथियों की आंखें नम हो गईं। स्वागत गीत, राधा गोरी-गोरी, चार युग, नारी शक्ति, अनपढ़ बहू, स्वच्छ भारत अभियान, शिव तांडव और

राज करेगा मलिक जैसी प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संतोष त्रिपाठी ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में गोपाल दास गुप्ता, अरविंद केसरवानी, पंकज गुप्ता, अनिल मिश्रा (एडवोकेट हाईकोर्ट), सोमनाथ वर्मा, आबिद अली, दीपक केसरवानी, आनंद द्विवेदी, रामानुज अग्रहरि, राजेश गुप्ता, अनूप केसरवानी, शिवराम सिंह परिहार, पप्पू सुसारी, पत्रकार आलोक गुप्ता, एसआई न्यूज के जोनल ब्यूरो चीफ प्रयागराज मनीष सुसारी, दैनिक जागरण के पत्रकार छेदीलाल, एन.एस.के. इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रताप बहादुर सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक धर्मराज कुशवाहा एवं इमरान अहमद ने संयुक्त रूप से किया। समारोह का समापन विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी बालेंद्र पांडे द्वारा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं समस्त स्टाफ की सक्रिय सहभागिता रही।

खुशहाल प्रसाद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया 13वां वार्षिक उत्सव

गोरखपुर। खुशहाल प्रसाद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज में 13वां वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान रहे। उनके आगमन

पर विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रतिभा सम्मान एवं खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शैक्षिक एवं खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। मंत्री श्री कमलेश पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और बेटियों की शिक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव है। कार्यक्रम में विद्यालय के मुख्य संस्थापक श्री राम आसारे निषाद ने अपने आशीर्वचन देते हुए बच्चों और अभिभावकों का मार्गदर्शन किया तथा विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और संस्कारों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सह निदेशक हरिकेश साहनी, प्रधानाचार्य अजय कनौजिया, खेल शिक्षक क्रांति सिंह, उप प्रधानाचार्य संध्या यादव, प्राइमरी की प्रधान अध्यापिका सीमा गौतम सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ और उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

UGC के काले कानून व संतों के अपमान के विरोध में जन समर्पण पार्टी का विशाल प्रदर्शन

गोरखपुर। UGC के कथित काले कानून को वापस लेने तथा संत समाज और सनातन धर्म के अपमान के विरोध में जन समर्पण पार्टी के तत्वावधान में 30 जनवरी को गोरखपुर में विशाल पदयात्रा एवं विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा गोरखपुर नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस पदयात्रा का नेतृत्व पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चन्द ने किया। उन्होंने कहा कि UGC का यह कानून समाज को दो भागों में बांटने वाला है और इससे शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक समरसता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में संत समाज और सनातन परंपराओं का लगातार अपमान हो रहा है, जिसे किसी

भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन में पार्टी के हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रमुख रूप से वीर सिंह (राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव), विकास राणा (जिला अध्यक्ष, गोरखपुर), जय सिंह (प्रभारी, गोरखपुर), कमलकांत गौड़ (प्रदेश संयोजक), अजय सिंह (आईटी हेड), चंद्र मौल मणि त्रिपाठी (जिला महासचिव), सत्य प्रकाश सिंह (जिला सचिव), अजय शर्मा (जिला सचिव), राजन गौड़, अभय शर्मा, राहुल सिंह, सुनील त्रिपाठी, राकेश सोनकर सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने वक्फ के काले कानून को वापस लेने और संतों के अपमान के मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पार्टी नेतृत्व ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इस पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

गोरखपुर मंडल के जनपदों के लिए एक जिला एक व्यंजन की शुरू हुई खोज

संवाददाता

गोरखपुर। "एक जिला एक उत्पाद" की तर्ज पर शासन ने गोरखपुर मंडल के सभी चार जिलों में "एक जिला एक व्यंजन" (ओडीओसी) के चयन का निर्णय लिया है। इसके लिए व्यंजनों की चिह्नित करने की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को दी गई है। डीडीयू प्रशासन ने इसे लेकर योजना तैयार कर ली है। इसके तहत विश्वविद्यालय प्रशासन गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर व महराजगंज जनपदों में हेरिटेज फूड फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। डीडीयू प्रशासन ओडीओसी के लिए इच्छुक लोगों से शासन के मानक के अनुरूप व्यंजन प्रस्तुत करने का आमंत्रण देगा। फेस्टिवल में प्रस्तुत व्यंजनों का मूल्यांकन उनकी ऐतिहासिकता, पारंपरिकता, निर्माण तकनीक, गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग की संभावनाओं जैसे मानकों पर किया जाएगा।

Massive Protest by Jan Samarpan Party Against UGC’s “Black Law” and Insult to Saints

Gorakhpur. A massive protest march and demonstration were organised in Gorakhpur on January 30 under the banner of the Jan Samarpan Party, demanding the withdrawal of the alleged “black law” of the UGC and protesting against the insult to the saint community and Sanatan Dharma. The march began from the Gorakhpur Municipal Corporation premises and proceeded to the District Magistrate’s office, where the protesters submitted a memorandum outlining their demands.“The protest was led by the party’s Founder and National President, Abhishek

Chand. Addressing the gathering, he said that the UGC law is divisive in nature and would have a negative impact not only on the education system but also on social harmony. He alleged that under the current system, the saint community and Sanatan traditions are being repeatedly insulted, which is unacceptable under any circumstances.“Thousands of party office-bearers and workers participated in the demonstration. Prominent among those present were Veer Singh (National Chief General Secretary), Vikas Rana (District President, Gorakhpur), Jai Singh (In-charge, Gorakhpur), Kamalkant Gaur (State Coordinator), Ajay Singh (IT Head), Chandra Maul Mani Tripathi (District General Secretary), Satya Prakash Singh (District Secretary), Ajay Sharma (District Secretary), along with Rajan Gaur, Abhay Sharma, Rahul Singh, Sunil Tripathi, Rakesh Sonkar, and many other party leaders and workers.“During the protest, participants demanded the immediate withdrawal of the UGC’s “black law” and strict action against those responsible for insulting saints. The party leadership warned that if the government fails to take concrete steps soon, the agitation will be intensified further.

No big-ticket sops for poll-bound states in Budget 2026, unlike previous years

Ahead of Assembly elections in Assam, West

Bengal, Kerala, and Tamil Nadu, the Union Budget made little to no mention of these poll-bound states, in a departure from five years ago, when they had received major allocations. The previous two Budgets had triggered political rows for their special emphasis on Bihar, which went to the polls late last year.

This year, Assam is among the six states where Buddhist circuits will be established, while Tezpur is set to get a regional centre of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS). Chennai and Siliguri in north Bengal were announced as hubs for high-speed rail corridors, while Kerala and Tamil Nadu will be part of a rare earth metals mining scheme, though no specific allocations were announced.

NDA years

In the 72 Assembly elections since 2014 (counting those happening this year), the Union Budget made specific allocations or announcements for 21 poll-bound states. Here are some instances:

2025-26: Ahead of the Delhi and Bihar Assembly elections, the Budget made special announcements for Bihar, just as it had the previous year when the third Narendra Modi government came to power after the 2024 Lok Sabha polls, while targeting Delhi with sops for the middle class. Bihar got a Makhana Board, a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, financial support for the Western Koshi Canal ERM Project for farmers in the Mithilanchal region, and funds for new airports and the expansion of Patna airport.

2024-25: While the interim Budget made no specific allocations for eight poll-bound states, the Budget that followed the NDA win in the Lok Sabha polls made special announcements for Andhra Pradesh and Bihar, where NDA constituents TDP and JD(U) ensured that the alliance crossed the majority mark in the Lower House.

The Budget allocated Rs 15,000 crore for the development of Andhra Pradesh’s own capital and committed to provide funds for the Polavaram Irrigation Project and the Vishakhapatnam-Chennai Industrial Corridor. Bihar, despite its elections being over a year away at the time, received Rs 26,000 crore for major road connectivity projects, Rs 21,400 crore for power projects, and Rs 11,500 crore for irrigation infrastructure.

2023-24: For Karnataka and Telangana, among the nine states where Assembly polls were scheduled that year, the Budget made a special allocation of Rs 5,300 crore for the Upper Bhadra Project to irrigate drought-prone areas of central Karnataka, besides designating Hyderabad’s Indian Institute of Millet Research as a “Centre of Excellence”. However, there were no specific announcements for Tripura, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan, all of which held Assembly polls that year.

2021-22: Five years ago, it was a bumper Budget for this year’s poll-bound states. The Budget allocated an additional Rs 34,000 crore for national highway projects in Assam, noting that projects worth Rs 19,000 crore were already underway. The Budget also provided Rs 1,000 crore for the welfare of tea plantation workers in Assam and West Bengal, which also received Rs 25,000 crore for highway projects.

13th Annual Function Celebrated with Grandeur at Khushhal Prasad Smarak Kanya Inter College

Gorakhpur. The 13th Annual Function of Khushhal Prasad Smarak Kanya Inter College was celebrated with great enthusiasm and dignity. The chief guest of the programme was Shri Kamlesh Paswan, Union Minister of State for Rural Development, Government of India. He was given a warm and cordial welcome by the college management and staff on his arrival.“On the

occasion, a Merit Award and Sports Award Ceremony was organised, in which students who excelled in academics and sports were honoured with prizes. Addressing the gathering, Minister Shri Kamlesh Paswan said that along with education, sports play a vital role in the all-round development of children, and that the education of girls forms the strong foundation of nation-building.“The chief founder of the institution, Shri Ram Asare Nishad, blessed the students and guided both students and parents. He inspired the students to move forward in life with discipline, hard work, and strong moral values.“Present on the occasion were Co-Director Harikesh Sahni, Principal Ajay Kanojia, Sports Teacher Kranti Singh, Vice Principal Sandhya Yadav, Primary Headmistress Seema Gautam, along with other teaching staff of the institution.“The programme concluded in an enthusiastic atmosphere, with the guests extending their best wishes for a bright and successful future for the students.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, शक्ति शंकर द्वारा फाईन आफसेट प्रिंटर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्शीपुर, जनपद-गोरखपुर से मुद्रित कराकर, मुहल्ला-द्वितीय तल पुष्पांजलि काम्प्लेक्स शाही मार्केट, गोलघर, जनपद-गोरखपुर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक :
शक्ति शंकर
मो नं.
7233999001
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा।